जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 27 संख्याः 55 प्रभात अजमेर, शुक्रवार 23 सितम्बर, 2022 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

एक नए डेटा के अनुसार गत 30 वर्षों में 11 लाख से अधिक सी टर्टल्स को अवैध रुप से मारा गया है। एरिज़ोना स्टेट युनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का अनुमान है कि, संरक्षण कानून होने के बावजूद गत एक दशक में 655 देशों में हर वर्ष 44000 कछुओं मारे गए हैं। एरिज़ोना स्टेट युनिवर्सिटी में असिस्टेंट रिसर्च प्रोफेसर तथा शोध की एक प्रमुख लेखक जैस्सी सैंको ने कहा, ''यह संख्या बहुत ही अधिक है लेकिन फिर भी वास्तविक संख्या से कम ही है। क्योंकि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि का आकलन कर पाना आसान नहीं होता।'' संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनुसार सी टर्टल का भोजन के लिए शिकार किया जाता है। इसके अलावा कलाकृतियां, घरेलू सज्जा और आभूषणों के लिए भी इन्हें पकड़ा जाता है। अवैध वाइल्डलाइफ मार्केट में टर्टल के अवैध व्यापार की हिस्सेदारी 23 अरब डॉलर है। टर्टल का अवैध शिकार कितना है इसे जानने के लिए शोधकर्ताओं ने विभिन्न जर्नल्स में छपे 209 आर्टिकल्स, मीडिया रिपोर्ट्स, संरक्षण संगठनों की रिपोर्ट्स आदि का अध्ययन किया तथा सभी साबुत टर्टल एवं टर्टल के बायप्रॉडक्ट्स, जैसे सिर, पूँछ, शैल आदि को भी देखा। शोध से पता चला कि 1990 से 2010 के बीच लगभग 43,000 टर्टल्स की तस्करी हुई, लेकिन यह अनुमान संभवतया मूल संख्या से फिर भी बहुत कम है। साउथ ईस्ट एशिया और मैडागास्कर सी टर्टल शिकार के ''हॉटस्पॉट'' हैं और सी टर्टल की लगभग सारी तस्करी वियतनाम से शुरु होती है। चीन व जापान सी टर्टल उत्पादों का सबसे लोकप्रिय बाजार हैं। सैंको कहते हैं, जब तक अमीर देशों में टर्टल के उत्पादों की मांग रहेगी तब तक विकासशील देश टर्टल की आपूर्ति करते रहेंगे। कई देशों में तो घरों में ''स्टफ्ड टर्टल'' रखना स्टेटस सिम्बल माना जाता है। जिन टर्टल्स का शिकार होता है उनमें 95 प्रतिशत संख्या ग्रीन टर्टल और हॉक्सबिल टर्टल की है। ओशनिक सोसायटी के अध्यक्ष रॉडरिक मास्ट ने बताया कि, ग्रीन टर्टल का मांस बेहद स्वादिष्ट माना जाता, इनका जो पल्प या मीट होता है उसे लोग बहुत पसंद करते हैं। वहीं, हॉक्सविल का उसके खूबसूरत शैल के लिए शिकार किया जाता है। ये प्रजातियां क्रमशः संकटग्रस्त व गंभीर रुप से संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध हैं। तथापि, रिपोर्ट से यह भी सामने आया है कि गत दस वर्षों में सी टर्टल का अवैध शिकार 28 प्रतिशत घटा है और इसका कारण है इस जीव को लगातार मिल रहा कानूनी संरक्षण।

आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया

राहुल गांधी के सख्त रवैये के कारण गहलोत होश में आये और कांग्रेस अध्यक्ष के साथ-साथ राजस्थान का मु.मंत्री बने रहने की अपनी मांग को ''ड्रॉप'' किया

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **गहलोत, जो गुरूवार की सुबह मुम्बई से कोच्चि पहुंचे थे, देर रात को राहुल गांधी के साथ दिल्ली लौटेंगे तथा गांधी परिवार के तीनों सदस्यों, सोनिया गांधी, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी से बात करेंगे तथा सचिन पायलट को मु.मंत्री बनने से रोकने का अंतिम प्रयास करेंगे।**
- **राजस्थान के मु.मंत्री पद के लिये चल रहे संघर्ष में फिलहाल पायलट, गहलोत से कुछ कदम आगे हैं।**
- **गहलोत सोनिया गांधी से मिले, उससे एक दिन पहले पायलट सोनिया गांधी से मिलकर राजस्थान की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करके अपना पक्ष पूरी तरह समझा कर केरल चले गये थे।**
- **राहुल गांधी से मिलने जब गहलोत कोच्चि पहुंचे, उससे पहले पायलट को, पदयात्रा में चलते-चलते राहुल को अपनी बात समझाने का पूरा अवसर मिला।**
- **बसपा नेता राजेन्द्र सिंह गुढ़ा ने भी पाला बदलते हुए, साफ कहा, जिस व्यक्ति को कांग्रेस हाई कमान मु.मंत्री बनाना उचित समझता है, बसपा से कांग्रेस में आये विधायक उसी का साथ देंगे।**

नई दिल्ली, 22 सितम्बर। आखिर ऊँट पहाड़ के नीचे आ ही गया!!

राहुल गांधी द्वारा अपनाये गये कड़े रुख के बाद, अशोक गहलोत अपने होशो-हवास में आ गये तथा उन्होंने अपनी यह माँग छोड़ दी कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष बनने के साथ-साथ, मुख्यमंत्री भी बना रहने दिया जाये।

गहलोत ने आखिरकार यह कह ही दिया कि वे दोनों पदों के साथ न्याय नहीं कर सकते तथा मुख्यमंत्री पद से हट जायेंगे।

गहलोत के रुख में यह परिवर्तन उस समय आया, जब राहुल गांधी ने केरल में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी उदयपुर चिन्तन शिविर में पारित ''एक व्यक्ति, एक पद'' के प्रस्ताव पर अमल करेगी। इसके बाद गहलोत ने हार मान ली तथा त्याग पत्र देने के लिए राजी हो गये।

लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर रखने की कोशिश अभी भी नहीं छोड़ी है।

गहलोत चाहते थे कि वे गांधी परिवार के तीनों सदस्यों से मिलकर, स्थिति पर चर्चा करें।

इसलिये, गहलोत, जो राहुल गांधी से मिलने आज सुबह मुम्बई से केरल पहुँचे थे, आज देर रात गये राहुल को दिल्ली ला रहे हैं। दिल्ली आने के बाद, आज देर रात गये तीनों गांधियों के साथ गहलोत की मीटिंग होगी।

यह सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोकने का गहलोत का अंतिम प्रयास होगा।

लेकिन वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जो राहुल गांधी के पक्ष में पूरी तरह मुखर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक और भारत जोड़ो यात्रा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **भारत जोड़ो यात्रा को मिले भारी समर्थन से उत्साहित कांग्रेस अगले वर्ष एक और भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन करेगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, जयराम रमेश ने कहा कि, यह यात्रा पूर्व से पश्चिम तक निकाली जाएगी।**

नई दिल्ली, 22 सितम्बर। भारत जोडो यात्रा, जो अभी केरल से गुजर रही है, को मिले जन समर्थन से उत्साहित कांग्रेस ने तय किया है कि अगले वर्ष पूर्व से पश्चिम तक इसी तरह की यात्रा आयोजित की जाएगी।

कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने केरल के न्जलकम जमात कान्वैंशन सैंटर में हुई एक प्रैस कॉन्फैस में कहा कि ऐसी ही एक और भारत जोड़ो यात्रा होगी जिसमें बिहार झारखंड और उत्तर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक हिजाब पर दो अलग-अलग कहानियां क्यों, कर्नाटक व तमिलनाडू में

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **कर्नाटक सरकार ने स्कूल युनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है।**
- **पर, तमिलनाडू में एक हैडमिस्ट्रेस ने दो मुस्लिम छात्राओं को अपना हिजाब उतार कर, अपने बैग में रखने के आदेश दिये तो, शिक्षा विभाग ने तुरंत स्कूल व हैडमिस्ट्रेस को साफ कहा कि, छात्राएं अपने आप निर्णय ले सकती हैं, उन्हें हिजाब पहनना है या नहीं तथा स्कूल प्रशासन की इस मुद्दे पर कोई भूमिका नहीं है।**
- **कर्नाटक सही है या तमिलनाडू, यह तो हिजाब के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही लम्बी सुनवायी के बाद, आने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही निर्धारित करेगा।**

नई दिल्ली, 22 सितम्बर। यह कहानी हिजाब और दो राज्यों-कर्नाटक एवं तमिलनाडू की है, जहां अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाएं दुपट्टा या स्कार्फ पहनती हैं। हिजाब का मुद्दा इन दोनों राज्यों की सरकारों की प्राथमिकताओं की और भी संकेत करता है। कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब पर रोक लगाने को महत्व दिया गया है, जो एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसमें दो समुदायों के बीच की शांति को गड़बड़ा देने की क्षमता है। वहीं इस मुद्दे पर पड़ोसी राज्य तमिलनाडू का सोच ठीक इसके विपरीत है। तमिलनाडू ने हिजाब पहनने के मामले में बालिकाओं की पसंद-नापसंद में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है।

कर्नाटक में हिजाब को लेकर काफी कुछ हुआ है। राज्य सरकार ने इस परम्परा पर सख्त रूख दिखाते हुए, इसके स्कूलों-कॉलेजों में पहने जाने पर पाबंदी लगा दी है तथा ऐसा करने के औचित्य के लिये स्कूल-कॉलेजों की यूनिफॉर्मों (जहां ये लागू हैं) से संबंधित नियमों-कानूनों का हवाला दिया है तथा अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से इसकी अपेक्षित प्रतिक्रिया सामने आई है। कर्नाटक के शहर और कस्बे जमीनी तनाव के साक्षी हैं तथा इसे लेकर अशोभनीय घटनाओं को रोकने के लिये सरकार को सुरक्षा व्यवस्था सख्त करनी पड़ी थी। हिजाब विवाद सर्वोच्च न्यायालय में भी पहुंच गया है।

प्रसंगवश बता दें, सर्वोच्च न्यायालय में हिजाब के विवाद लम्बी कानूनी कार्यवाही चली है तथा सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद, अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'द तिरूमला गाइड'

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **तिरूपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट अब मंदिर में आने वाले भक्तों की आम समस्याओं को दूर करने के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। ट्रस्ट ने ''तिरूमला गाइड'' नाम का एक मोबाइल एप बनाया है, जिससे अलग-अलग भाषाओं वाले श्रद्धालुओं को मदद मिल सकती है।**

नई दिल्ली, 22 सितम्बर। इसमें कोई अचरज नहीं है कि आंध्र प्रदेश के चितूर जिले के तिरुपति बालाजी मंदिर ने भी समस्याओं से निजात पाने के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का सहारा लिया है। आंध्र प्रदेश सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में विकास के लिए जाना जाता है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम् ट्रस्ट जो कि वैटिकन के बाद विश्व के दूसरे सबसे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'निर्धन सवर्णों को दिया गया 10 प्रतिशत आरक्षण हर प्रदेश में अगल-अलग होगा'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **एटॉर्नी जनरल व सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि, सरकारी नौकरी व उच्च शिक्षा में दिया गया यह आरक्षण स्थायी नहीं है, क्योंकि राज्य की आर्थिक परिस्थिति देखते हुए लागू होगा और माली हालत ठीक होने पर आरक्षण वापस भी लिया जा सकता है।**
- **यह भी तर्क दिया गया कि, इस आरक्षण की सुविधा में केवल निर्धन सवर्ण ही शामिल हैं और एस.सी., एस.टी. व ओ.बी.सी. नहीं, क्योंकि इन तीनों वर्गों को पहले ही 50 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है और ढाई-ढाई प्रतिशत आरक्षण जोड़ा गया तो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन होगा।**

नई दिल्ली, 22 सितम्बर। केन्द्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सवर्ण जातियों के इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन्स (ई.डब्ल्यु.एस.) के लिए आरक्षण 10 प्रतिशत तक है, जिसका मतलब है कि यह उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर राज्य दर राज्य अलग-अलग हो सकता है।

ई.डब्ल्यु.एस. को आरक्षण उपलब्ध करवाने वाले संविधान के 103वें संशोधन का पक्ष लेते हुए अटॉर्नी जनरल के.के. वेगुगोपाल के चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस एस. रविन्द्र भट, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जे.बी. पारदीवाला से युक्त पांच जजों की संविधान बैंच को बताया कि ई.डब्ल्यु.एस. आरक्षण उन आर्थिक कठिनाईयों का समाधान करने के लिए है जो जनरल कैटेगरी की आबादी के 18.2 करोड़ गरीब लोगों को उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने और सरकारी नौकरियां लेने से रोकती हैं। उन्होंने कहा कि एस.सी. और एस.

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'जो फैसला हाई कमान करेगा हम उसके साथ हैं'

- **बसपा नेता राजेन्द्र गुढ़ा ने राजस्थान में सरकार का तख्ता पलटने पर अपना ''स्टैण्ड'' स्पष्ट किया।**

जयपुर, 22 सितम्बर (का.प्र.)। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तथा उनके स्थान पर नया मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चाओं के बीच राजस्थान के विधायकों के सुर बदलने लगे हैं।

अब तक मुख्यमंत्री खेमे के साथ रहे और अपने बयानों को लेकर चर्चित बसपा से जीतकर कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायकों ने भी अपना पुराना स्टैंड बदलने के संकेत दे दिए हैं और कहा है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, वह उसके साथ हैं।

सचिन पायलट या किसी दूसरे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मैं किसी के नाम की न चर्चा करता हूँ न कर रहा हूँ, देखना यह है कि, कौन आए, जिससे पार्टी एकजुट रहे और सरकार रिपीट हो'

गहलोत ने यह भी कहा कि, अध्यक्ष का पद, एक व्यक्ति एक पद के दायरे में नहीं आता, लेकिन इतिहास में कोई कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं रहा, इसलिए फैसला करना पड़ा

- **पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा, जो हालात राजस्थान के अंदर हैं, हाई कमान स्टडी करेगा और देखेगा कि, विधायकों की क्या भावना है।**
- **इस बीच उप मुख्यमंत्री पद के लिए गोविंद डोटासरा और शांति धारीवाल के नाम की चर्चा शुरू हुई, वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ब्राह्मण चेहरा लाने की बात हो रही है।**

जयपुर, 22 सितम्बर (का.प्र.)। राहुल गांधी ने गुरुवार को कोच्चि में पार्टी अध्यक्ष पद के दावेदार और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, पार्टी अध्यक्ष पद और मुख्यमंत्री पद, दोनों अपने पास रखने की इच्छा के विपरीत कहा कि, उदयपुर अधिवेशन में एक व्यक्ति एक पद पर हमने जो फैसला किया था, वह कायम रहेगा। दूसरी ओर सचिन पायलट के नाम पर ऐतराज होने के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, ''मैं किसी के नाम की न चर्चा करता हूं और न कर रहा हूं। हमें यह देखना है कि कौन आए, जिससे मैसेज जाए कि पार्टी एकजुट है और हम किसी भी कीमत पर सरकार रिपीट करें। जिससे अन्य राज्यों में भी पार्टी फिर से खड़ी हो। यह बहुत बड़ा फैसला होगा और यह सोच-समझकर लेना पड़ेगा।''

दरअसल यह सवाल इसलिए आया क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि, अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी को लाया जा सकता है। इसका कारण यह बताया जा रहा है कि, जोशी राहुल गांधी के साथ काम कर चुके हैं और उनके रहते अशोक गहलोत खेमा किसी तरह की नाराजगी नहीं जताएगा।

मुख्यमंत्री गहलोत ने एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंचने पर कहा था कि, एक व्यक्ति एक पद वाला नियम नॉमिनेटेड पोस्ट पर लागू होता है। लेकिन पहले दिग्विजय सिंह ने कहा, फिर, गुरुवार को राहुल गांधी ने उदयपुर डैक्लरेशन के अनुसार एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला लागू होने पर मोहर लगा दी, जिसके बाद गहलोत ने गुरुवार को कह दिया कि, अध्यक्ष का पद, एक व्यक्ति एक पद के दायरे में नहीं आता, लेकिन इतिहास में कोई कांग्रेस अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं रहा, इसलिए फैसला करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि, मुख्यमंत्री को लेकर फैसला, विधायकों की मर्जी जैसी होगी वैसे होगा। हालांकि यह बात लागू इसलिए नहीं होती है, क्योंकि कांग्रेस में हमेशा विधायक दल की बैठक में फैसला आलाकमान पर छोड़ा जाता है और आलाकमान जिस नाम पर मुहर लगाता है वही मुख्यमंत्री बनता है। खुद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तब भी हमेशा इसी तरह से फैसला होता रहा है। ऐसे में विधायक दल की बैठक होना मात्र औपचारिकता ही रहेगी और फैसला, जैसा गांधी परिवार चाहेगा वैसा ही होगा।

इधर कोच्चि पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की राहुल गांधी से चर्चा हुई। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी कोच्चि पहुंचे और राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर बदलाव होना तो निश्चित है, लेकिन अब राजस्थान में दो उप मुख्यमंत्री बनाए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)